

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246280
SG-DL-E-05062023-246280असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 85
No. 20]	DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JAISHTHA 15, 1945	[N. C. T. D. No. 85

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जून, 2023

फा. सं. 50/नियम/दि.उ.न्या.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय में विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति हेतु योजना जो कि दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV, सं. 22 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 424), दिनांकित 20.01.2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 38/नियम/दि.उ.न्या., दिनांकित 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित और दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV, सं. 344 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 319), दिनांकित 09.12.2019 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 742/नियम/दि.उ.न्या., दिनांकित 06.12.2019 द्वारा पुनः संशोधित तथा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-I, सं. 1 (रा.रा.क्षे.दि. सं. 460), दिनांकित 17.02.2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 04/नियम/दि.उ.न्या., दिनांकित 16.02.2022 द्वारा पुनः संशोधित में एतद्वारा दिनांक 05.04.2023 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

वर्तमान पैरा 7 एवं 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“2. विधि शोधकर्ताओं की सेवाओं हेतु हकदारी:

दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं प्रत्येक माननीय न्यायाधीश चार विधि शोधकर्ताओं की सेवाएँ लेने के

हकदार होंगे।”

“7. पारिश्रमिक:

एलआर को समय-समय पर यथा निर्धारित/संशोधित एक निश्चित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

एलआर किसी अन्य भत्ते या अनुलाभों का हकदार नहीं होगा।”

न्यायालय के आदेशानुसार,

रविंदर डुडेजा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd June, 2023

F. No. 50/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice hereby makes the following amendment, with effect from 05.04.2023, in the Scheme for engagement of Law Researchers in the High Court of Delhi notified vide Notification No. 38/Rules/DHC dated 19.01.2018, published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 22 (N.C.T.D. No. 424) dated 20.01.2018 and further amended vide Notification No.742/Rules/DHC dated 06.12.2019, published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 344 (N.C.T.D. No. 319) dated 09.12.2019 and further amended vide Notification No. 04/Rules/DHC dated 16.02.2022, published in Delhi Gazette Extraordinary Part II, Section I, No.1 (N.C.T.D. No. 460) dated 17.02.2022:

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PARA 2 AND 7:-

“2. Entitlement for the Services of Law Researchers:

Hon'ble the Chief Justice and each Hon'ble Judge of Delhi High Court shall be entitled to have services of four Law Researchers”.

“7. Remuneration:-

An LR shall be paid a fixed monthly honorarium as fixed/revised from time to time. The LR shall not be entitled to any other allowance or perks”.

By Order of the Court,

RAVINDER DUDEJA, Registrar Gen.